जयपुर • कोटा • बीकानेर • उदयपुर • अजमेर • जालोर • हिण्डौनसिटी • चूरू

राष्ट्रदूत

epaper.rashtradoot.com

चूरू

Rashtradoot

फोनः- 256906, 256907, फैक्सः- 01562-256908 वर्षः 16 संख्याः 321 प्रभात चूरू, शुक्रवार 21 मार्च, 2025 पो. रजि. न. चूरू/084/2019-21 पृष्ठ 6 मूल्य 2.50 रु.

पुतिन ने अगूंठा दिखाया अमेरिका के तीस दिन के युद्ध विराम के प्रस्ताव को

रूस युद्ध विराम पर बातचीत के लिए आने को तैयार नहीं होगा, जब तक उसका दीर्घकालीन उद्देश्य पूरा नहीं होता

-अंजन रॉय-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 20 मार्च। अमेरिका के राष्ट्रपति ने अनेक प्रयास किए, रुस के राष्ट्रपति को अनेक रियायतें दीं, यू.एन. में यूक्रेन युद्ध पर, नॉर्थ कोरिया, ईरान और रुस के साथ वोट भी किया, लेकिन, इसके बावजूद पुतिन ने अमेरिकी राष्ट्रपति के साथ धोखाधड़ी की है।

रुस के राष्ट्रपति ने, डॉनल्ड ट्रंप के, 30 दिनों के तत्काल युद्धविराम प्रस्ताव को सीधे तौर पर ठुकरा दिया है। यूक्रेन ने पहले ट्रंप के इस प्रस्ताव को मान लिया था। अब यह स्पष्ट हो गया है कि पुतिन, युद्ध को रोकने के ट्रंप के प्रयासों के तहत किसी भी प्रस्ताव को मानने के मूड में नहीं हैं।

डॉनल्ड ट्रंप ने वादा किया था कि यदि पुतिन युद्धविराम पर बातचीत में शामिल नहीं होते हैं तो अमेरिका रुस पर कड़े प्रतिबंध लगाएगा। इसमें दो अलग तरह के एक्शन शामिल हैं।

पहला, आर्थिक प्रतिबंध लागू करना, ताकि, रुसी अर्थव्यवस्था को आत्मसमर्पण करने के लिए मजबूर किया जा सके। रुस पहले ही उन गंभीर प्रतिबंधों के दबाव में है, जो अब तक लागू किए गए हैं, जैसे बैंकिंग लेन-देन पर प्रतिबंध और रुस के मुख्य निर्यातों में मुक्त व्यापार पर प्रतिबंध।

- सोवियत यूनियन के विघटन से पूर्व रूस ''ब्लैक सी'' को अपना निजी तालाब ही मानता था।
- पर, सोवियत यूनियन के विघटन के बाद, रूस ने ''ब्लैक सी'' पर नियंत्रण खो दिया तथा उससे सटे हुए देश रोमानिया व बल्गेरिया भी पश्चिमी देशों के प्रभाव में चले गये तथा टर्की नाटो का एक महत्वपूर्ण सदस्य हो गया।
- अतः, रूस के दीर्घकालीन उद्देश्य में ''ब्लैक सी'' पर पुनः नियंत्रण स्थापित करना है और इसीलिए यूक्रेन के प्रमुख बंदरगाह ओडेसा को भी हथियाना चाहता है।
- रूस, जब तक अपने दीर्घकालीन उद्देश्यों की पूर्ति नहीं कर लेता, यूक्रेन में युद्ध विराम करने को तैयार नहीं होगा।
- अमेरिका भी अब रूस के इस उद्देश्य को समझ रहा है, पर, अमेरिका के पास कोई अन्य विकल्प नहीं है, इसके अलावा कि, रूस पर और दबाव बनाये कि वह युद्ध विराम के लिये बातचीत के लिये आये।
- रूस पर दबाव बनाने के लिये अमेरिका ने यूक्रेन से ''इन्टैलिजैंस'' साझा करना पुनः शुरु कर दिया है और रूस पर और सख्त आर्थिक प्रतिबंध लगाये हैं।

इन प्रतिबंधों और नियंत्रणों ने रुस के सबसे महत्वपूर्ण निर्यात, ऊर्जा उत्पादों की बिक्री को प्रभावित किया है। इन प्रतिबंधों ने रुसी क्रूड ऑयल और प्राकृतिक गैस की कीमतों पर दबाव डाला है। इनकी खपत भी प्रभावित हुई है, क्योंकि, कुछ प्रमुख खरीददार अब रुसी तेल और गैस से मुँह मोड़ चुके हैं।

दूसरा, अमेरिकियों ने यूक्रेन के युद्ध प्रयासों के लिए अति महत्वपूर्ण, खुफिया जानकारी की आपूर्ति रोकने का प्रयास किया था। अमेरिकी खुफिया जानकारी के बिना यूक्रेन की आक्रमण की रणनीतियों पर असर पड़ा था। यह निर्णय, जैलैंस्की की ओवल ऑफिस में डॉनल्ड ट्रंप के साथ हुई आपत्तिजनक बैठक के बाद लिया गया था।

लेकिन, अब जबकि, रुस का अड़ियल रवैया पूरी तरह सामने आ गया है, तो अमेरिकियों ने खुफिया जानकारी की आपूर्ति को फिर से तेज कर दिया है। इसके परिणामस्वरुप, यूक्रेनी सैनिकों ने रुस के क्षेत्र में 500 मीटर अंदर एक एयरबेस पर हमला किया। रुस इस एयरबेस पर अपने परमाणु क्षमता वाले बमवर्षकों को रखता है। इंगलेस टाउन के इस एयरबेस पर रुस के टूपोलेव परमाणु हथियार क्षमता वाले विमान हैं। इस एयरबेस का मुख्य रनवे अब उपयोग

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

वरिष्ठ अध्यापक परीक्षा चीटिंग, दो आरोपी गिरफ्तार

जयपुर, 20 मार्च। स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप (एसओजी) ने कार्रवाई करते हुए राजस्थान लोकसेवा आयोग अजमेर की ओर से आयोजित वरिष्ठ अध्यापक परीक्षा विषय विज्ञान 2022 में डमी कैंडिडेट बैठा कर परीक्षा दिलवाने वाले दो आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। फिलहाल आरोपियों से पूछताछ की जा रही है।

अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक एटीएस और एसओजी वी.के सिंह ने बताया कि एसओजी की टीम ने गुरुवार को कार्रवाई करते हुए राजस्थान लोकसेवा आयोग अजमेर की ओर से आयोजित वरिष्ठ अध्यापक परीक्षा

- आरोप है कि इन्होंने दो अभ्यर्थियों की जगह डमी कैन्डिडेट से परीक्षा दिलवाई थी।

विषय विज्ञान 2022 में डमी कैंडिडेट बैठा कर परीक्षा दिलवाने वाले प्रवीण कुमार (23) निवासी धनाउ जिला बाड़मेर हाल द्वितीय श्रेणी अध्यापक (विषय विज्ञान) राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय इटादा मनाउ जिला बाड़मेर और देवाराम बिश्नोई (27) निवासी चितलवाना जिला जालौर हाल द्वितीय श्रेणी अध्यापक (विषय विज्ञान) राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, मुकने का ताला, धोरीमन्ना जिला बाड़मेर को गिरफ्तार किया है। इस संबंध में पुलिस निरीक्षक एसओजी जयपुर राजस्थान सीमा पठान ने 25 अक्टूबर 2024 को मामला दर्ज करवाया था, जिसमें बताया गया था कि राजस्थान

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

डी.एम.के. के सांसद ''डीलिमिटेशन विरोधी'' नारे लिखी टी-शर्ट पहनकर सदन में आये

लोकसभा अध्यक्ष ओम बिड़ला ने व्यवस्था दी, जब तक सांसद नारे लिखी टी-शर्ट पहन कर संसद में आयेंगे, सदन नहीं चलेगा

-डॉ. सतीश मिश्रा-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 20 मार्च। गुरुवार को संसद के दोनों सदनों में कार्यवाही इसलिये स्थगित कर दी गई, क्योंकि विपक्षी सदस्य सदन में टी-शर्ट पहन कर आये थे तथा इन पर संसदीय और विधानसभा क्षेत्रों के परिसीमन के मुद्दे के विरोधी नारे लिखे हुये थे।

टी-शर्ट पहने हुये सांसदों को देखकर उत्तेजित हुये लोकसभा अध्यक्ष ओम बिड़ला ने नारे लिखी हुई टी-शर्ट पहने हुये सांसदों को निर्देशित किया कि वे सदन से बाहर निकल जायें तथा उचित ड्रैस पहनकर आयें और सदन की गरिमा बनाये रखें।

बिड़ला ने कहा, ''कुछ सदस्य सदन की गरिमा एवं पवित्रता का खयाल नहीं रख रहे हैं।'' उन्होंने जोर देते हुये कहा कि टी-शर्ट पहनना संसदीय मर्यादा का उल्लंघन है। उन्होंने सासंदों से कहा, ''अगर आप नारे लिखी हुई टी-शर्ट पहन कर सदन में आयेंगे, तो सदन नहीं चलेगा। जब आप टी-शर्ट की जगह उचित वस्त्र पहन कर आयेंगे, तभी सदन चलेगा।''

द्रमुक सांसद जो सफेद टी-शर्ट पहने हुये थे, उन पर लिखा हुआ था, ''तमिलनाडु परिसीमन से लड़ेगा, तमिनलाडु जीतेगा।''

- डी.एम.के. सांसद काफी समय से ''डीलिमिटेशन'' का मुद्दा सदन में उठाने का प्रयास कर रहे हैं, पर, लोकसभाध्यक्ष ने उनको यह मुद्दा उठाने की इजाज़त नहीं दी है। लोकसभाध्यक्ष का तर्क है कि यह ''डीलिमिटेशन'' का मुद्दा अभी सरकार के एजेण्डे में नहीं है, क्योंकि अभी तो जनगणना भी नहीं हुई है। अतः जनगणना के बिना ''डीमिलिटेशन'' होने का सवाल ही कहाँ उठता है।

विपक्ष संसद में विरोध के सांधन के रुप में अपने वस्त्रों का उपयोग पहले भी कर चुका है, और इसको लेकर सदन में हो-हल्ला भी हुआ है। दिसम्बर, 2024 में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी तथा वायनाड सांसद प्रियंका गांधी टी-शर्ट पहन कर संसद में पहुँचे थे, जिन पर पीछे अडानी-विरोधी नारे छपे हुये थे।

उन दोनों की टी-शर्ट उद्योगपति गौतम अडानी के खिलाफ विरोध - प्रदर्शन का प्रतीक थीं, तथा युक्तिपूर्वक अप्रत्यक्ष संकेत कर रही थीं कि उनके (अडानी) के प्रधानमंत्री मोदी के साथ नजदीकी सम्बंध हैं।

उधर, राज्यसभा में सभापति जगदीप धनखड़ ने दिन में जल्दी ही सदन की कार्यवाही एक घंटे के लिये, दोपहर 12 बजे तक के लिये स्थगित कर दी तथा विभिन्न पार्टियों के फ्लोर लीडर्स की मीटिंग बुलाई।

जहाँ धनखड़ ने स्थगन का कोई कारण नहीं बताया, वहीं द्रमुक सदस्यों द्वारा नारे लिखी हुई टी-शर्ट पहनने के मुद्दे पर सभापति ने आपत्ति जरुर जताई।

बिड़ला ने इस मुद्दे पर सदन को पहले दोपहर 12 बजे तक के लिये स्थगित किया। जब सदन की बैठक 12 बजे पुनः शुरु हुई, तो तेलुगू देशम पार्टी (टीडीपी) सांसद कृष्ण प्रसाद तेन्नेती, जो सदन की अध्यक्षता कर रहे थे, ने लोकसभा की कार्यवाही अपरान्ह 2 बजे तक के लिये स्थगित कर दी।

द्रमुक सांसद लोकसभा में परिसीमन का मुद्दा उठाने की कोशिश करते आ रहे हैं, लेकिन लोकसभा अध्यक्ष ने उनके अनुरोध को यह कहते हुये अस्वीकार कर दिया है कि यह मुद्दा सरकार के राडार पर कहीं है ही नहीं,

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

तमिलनाडु सरकार की शराब बेचने वाली कंपनी पर ईडी ने रेड की

कर्मचारियों को साठ घंटे ऑफिस में बिठाये रखने का आरोप लगाया राज्य सरकार ने

- लक्ष्मण वैकेट कुची -
- राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो -

नई दिल्ली, 20 मार्च। एनफोर्समैंट डायरैक्टोरेट (ईडी), जिसने तमिलनाडु स्टेट मार्केटिंग कॉरपोरेशन (टी ए एस एम ए सी) पर शराब कंपनी में एक हजार करोड़ रुपये के घोटाले के आरोप में रेड की है, के मुद्दे पर करारा तमाचा जड़ते हुए, मद्रास हाईकोर्ट ने रेड के दौरान ईडी के व्यवहार की कड़ी निंदा की है।

तमिलनाडु, जहां एक साल में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, में ईडी एक्टिव हो गया है। ई डी ने यह कार्यवाही राज्य सरकार की शराब कंपनी में भाजपा द्वारा एक हजार करोड़ का घोटाला होने का आरोप लगाने पर की है। भाजपा ने स्टालिन को नम्बर वन आरोपी बताया है।

ईडी ने शहर में टी ए एस एम ए सी परिसर पर रेड की व तलाशी अभियान चलाया, जिस पर उसका तमिलनाडु सरकार से न्यायाधिकार क्षेत्र का विवाद हो गया और यह मसला अब हाईकोर्ट में है।

- रेड का कारण बताया जाता है, कंपनी में 1,000 करोड़ रूपए का स्कैम होना।
- भाजपा ने यह आरोप लगाते हुए कहा था कि सरकारी कंपनी, हर ग्राहक से अधिकतम रिटेल कीमत से 10 से 30 रूपये प्रति बोतल ज्यादा चार्ज कर रही थी। और यह रकम साल भर में 1,000 करोड़ रूपए हो जाती है तथा भाजपा के अनुसार, यह पैसा सीधे मुख्यमंत्री के पास जाता है। अतः मु.मंत्री इस स्कैम में नम्बर वन आरोपी हैं।

हाई कोर्ट की दो सदस्यीय बैंच ने टी ए एस एम ए सी की याचिका पर ईडी अधिकारियों को खूब लताड़ा, क्योंकि ईडी अधिकारियों ने टी ए एस एम ए सी कर्मचारियों को बंधक बना लिया और तलाशी व रेड का कोई कारण नहीं बताया।

जस्टिस एम एस रमेश और एन. सैंथिल कुमार की बैंच ने कहा ''क्या यह चिंताजनक स्थिति नहीं है। अगर आपके पास खास जानकारी है तो हम समझ सकते हैं, पर क्या आप सारे स्टाफ को कई घंटों तक अपने कब्जे में रख सकते हैं। अगर आपके पास कोई कारण था तो क्या आपको उन्हें नहीं बताना चाहिए था? उनकी यही शिकायत है कि उन्हें नहीं पता कि ईडी ने रेड क्यों की थी।

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

वन रक्षक भर्ती परीक्षा, फॉरेस्ट गार्ड रेशमी चिल्का गिरफ्तार

जयपुर, 20 मार्च। स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप (एसओजी) ने वन रक्षक पेपर लीक मामले में कार्रवाई करते हुए, वन रक्षक रेशमी कुमारी चिल्का को गिरफ्तार किया है। पुलिस जांच में सामने आया है कि इस महिला ने पांच लाख रुपए में सॉल्वड पेपर खरीदकर पढ़ा था।

- गहलोत सरकार के कार्यकाल में हुई इस परीक्षा में रेशमी चिल्का ने 5 लाख रूपए में सॉल्वड पेपर खरीद कर परीक्षा दी थी।

अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक एसओजी वीके सिंह ने बताया कि 30 जून 2024 को पुलिस थाना राजतलाब जिला बांसवाड़ा की आसेर से 13 नवम्बर 2022 की दोनों पारियों में हुई वन रक्षक भर्ती परीक्षा- 2020 का पेपर लीक होने की जानकारी मिलने पर प्रकरण की जांच एसओजी राजस्थान जयपुर की ओर से की जा रही है। इस

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

'गहलोत मीडिया की सुर्खियों में रहने के लिए नैगेटिव बातें करते हैं'

संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल ने अशोक गहलोत को आईना दिखाया

जयपुर, 20 मार्च। संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल ने विधानसभा में मीडिया को संबोधित करते हुए कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत मीडिया की सुर्खियों में रहने के लिए ही नैगेटिव बोलते हैं। वे अनावश्यक बात कर के सिर्फ सुर्खियों में रहने का काम करते हैं, मुद्दों पर बात नहीं करते। वे विधानसभा आए, पर सदन में नहीं आए, बस मीडिया के सामने ही उपस्थित रहे। उन्हें विधानसभा में आकर मुद्दों पर बात करनी चाहिए। उनको सरदारपुरा की जनता ने मौका दिया, पर वे सदन के अंदर तक नहीं आए। वे सिर्फ कांग्रेस की गुटबाजी को हवा देने का काम करते हैं।

जोगाराम पटेल ने कहा कि राजस्थान में मुख्यमंत्री और भाजपा की सरकार कांग्रेस के रहमो-करम पर नहीं बनी है कि पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी उसे मौका देंगे। सचिन पायलट को मुख्यमंत्री क्यों नहीं बनने दिया, उनको मौका क्यों नहीं दिया? पायलट को मौका देने की बजाय रगड़ाई की बात क्यों की? मौका देने की बजाय होटलों में कैम्पिंग क्यों की? परसराम मदेरणा , सीपी जोशी को मौका क्यों नहीं दिया गया? गहलोत जी, आपने 25 सितंबर 2022 को जयपुर आए कांग्रेस अध्यक्ष के दूत मल्लिकार्जुन खड़गे को नाटक रच कर विधायकों से मिलने का मौका क्यों नही दिया? जोगाराम पटेल ने कहा कि राजस्थान की जनता ने आपकी पार्टी को एक बार 1998 में मौका दिया था, पर आपने अन्य योग्य नेताओं को आगे बढ़ने का मौका नहीं दिया। उन्होंने कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी टीकाराम जूली जी को मौका क्यों नहीं दे रहे बोलने का। गहलोत जी जब विधानसभा के बाहर धरने पर बैठे थे, पायलट जी भी साथ थे, तब उन्होंने पायलट से हाथ मिलाकर उन्हें गले मिलने का मौका क्यों नहीं दिया?

- पटेल ने कहा, भाजपा सरकार कांग्रेस के रहमो करम पर नहीं बनी है, जो गहलोत मौका देगें।
- पटेल ने कहा, गहलोत ने खुद किसी को भी मौका नहीं दिया, हमने नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली को बोलने का मौका दिया तो गहलोत विधानसभा आ गए उनको काउन्टर करने।
- उन्होंने कहा कि गहलोत विधानसभा आए, पर, सदन में नहीं आए, उन्हें सरदारपुर की जनता ने मौका दिया, पर, वे सिर्फ कांग्रेस में गुटबाजी को हवा देने का काम करते हैं।

जोगाराम पटेल ने कहा कि कांग्रेस पार्टी ने इस बार टीकाराम जूली को नेता प्रतिपक्ष बनाया, पर गहलोत उन्हें सदन में बोलने तक का मौका नहीं देते। राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा के दौरान जूली का नंबर आया तो उन्हें बोलने नहीं दिया गया। लेकिन हमने उन्हें, विभिन्न विषयों पर सदन में बोलने का मौका दिया, इसका काउंटर करने आज गहलोत जी विधानसभा आए। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में सरकार शानदार काम कर रही है। राजस्थान के बजट की क्रियान्विति, युवाओं को रोजगार देने जैसे काम मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जी के कुशल मार्गदर्शन में हो रहे हैं। विधानसभा सही चले, जनता के मुद्दों पर चर्चा हो, सरकार यही चाहती है। जोगाराम पटेल ने कहा कि मैं पुनः आग्रह करता हूं कि गहलोत सदन में आएं, सदन की कार्यवाही में हिस्सा लें, राजस्थान की 8 करोड़ जनता से जुड़े विषयों पर चर्चा करें।

30 अप्रैल से शुरू होगी चार धाम यात्रा

देहरादून, 20 मार्चउत्तराखंड में चारधाम यात्रा और हेमकुंड साहिब के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन गुरुवार को शुरू हो गए। अधिकारियों ने बताया कि बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री के हिमालयी मंदिरों और हेमकुंड साहिब के सिख तीर्थस्थल पर जाने के इच्छुक भक्त अब उत्तराखंड पर्यटन विकास परिषद की वेबसाइट पर

- उत्तराखंड सरकार ने चार धाम और हेमकुंड साहिब की यात्रा के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन शुरू कर दिए हैं।

जाकर पंजीकरण कर सकते हैं। चारधाम यात्रा 30 अप्रैल को उत्तरकाशी जिले में गंगोत्री और यमुनोत्री मंदिरों के कपाट खुलने के साथ शुरू होगी। रुद्रप्रयाग जिले में केदारनाथ 2 मई को भक्तों के लिए खोला जाएगा, जबकि बद्रीनाथ 4 मई और चमोली जिले में हेमकुंड

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

क्या श्री शुभम लॉजिस्टिक को ''120 करोड़ रूपए'' का अवांछित लाभ दिलाने वाले सरकारी अधिकारियों पर आखिरकार गाज़ गिरेगी?

कृषि मंत्री किरोड़ी लाल मीणा ने जिन अधिकारियों को नामजद करते हुए मुख्यमंत्री को पत्र लिखा था, अब उनके खिलाफ जाँच शुरु करने के लिए ए.सी.बी. ने राज्य भंडारण निगम से अनुमति ले ली है

-यादवेन्द्र शर्मा-

जयपुर, 20 मार्च। राज्य के कृषि मंत्री किरोड़ी लाल मीणा ने गत अशोक गहलोत सरकार के कार्यकाल में सार्वजनिक वितरण की जाने वाली कृषि उपज के भंडारण में भारी घोटाले के संबंध में जो पत्र लिखा था, उस पत्र के संदर्भ में एन्टी-करप्शन ब्यूरो ने अब लगभग 10 महीने बाद राज्य भंडारण निगम में प्रतिनियुक्ति में कार्य कर चुके दो सरकारी अधिकारियों विश्वास पारीक तथा योगेश कुमार वर्मा के खिलाफ जाँच शुरु करने के लिए राज्य भंडारण निगम से अनुमति प्राप्त कर ली है।

जैसा कि विदित है, मंत्री किरोड़ी लाल ने 16 मई 2024 को मुख्यमंत्री को लिखे पत्र में गंभीर आरोप लगाये थे कि गहलोत सरकार के दौरान कृषि उपज के भंडारण के लिए श्री शुभम लॉजिस्टिक के साथ अनुबंधन किया गया था। इस कंपनी को 120 करोड़ रूपए का अवांछित लाभ गहलोत सरकार के अफसरों की मिलीभगत से दिया गया और राज्य सरकार के भंडारण निगम को करीब 200 करोड़ रूपए का नुकसान उठाना पड़ा।

- उल्लेखनीय है कि यह दो कर्मचारी राज्य भंडारण निगम में प्रतिनियुक्ति पर आये थे और अब अपने विभागों में लौट चुके हैं। इसलिए जाँच आगे बढ़ाने के लिए ए.सी.बी. को राज्य सरकार के कृषि विभाग और अधीनस्थ प्रशासनिक सेवाओं से संबंधित विभाग से भी अनुमति लेनी होगी।
- गौरफरमाने योग्य है कि कृषि मंत्री ने पिछले वर्ष मई में मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर बताया था कि पिछली गहलोत सरकार में कृषि उपज के भंडारण में भारी अनियमितताएँ हुई थीं और श्री शुभम लॉजिस्टिक, जो गहलोत की करीबी कंपनी है, को 120 करोड़ रूपए का अवांछित लाभ दिया गया था।
- हैरानी की बात है कि कृषि मंत्री के पत्र लिखे जाने के बाद ए.सी.बी. ने इस मामले में ''प्रिलिमिनरी इन्क्वायरी'' तो शुरु कर दी थी परन्तु लगभग 9 महीने बाद तक किसी भी सरकारी अधिकारी के खिलाफ न तो जाँच आरंभ की और न ही कोई एफ.आई.आर. दर्ज की।

इस पत्र में मीणा ने आरोप लगाया था कि श्री शुभम लॉजिस्टिक ने अनुबंधों की शर्तों का उल्लंघन करते हुए 3,000 करोड़ रूपए के मूल्य से भी अधिक की कृषि उपज का इंश्योरेंस (बीमा) नहीं कराया। ऐसी स्थिति में, किसी दुर्घटना, आपदा या कालाबाज़ारी से किसानों को अवांछित भारी नुकसान झेलना पड़ सकता था। इसके अतिरिक्त, मीणा ने पत्र में आरोप लगाया था कि श्री शुभम लॉजिस्टिक ने अनुबंध के अनुसार कई खर्चों का और बैंक गारंटी का भुगतान नहीं किया, जिससे निगम को करोड़ों का नुकसान हो गया। मीणा ने पत्र में लिखा था कि श्री शुभम लॉजिस्टिक अशोक गहलोत के करीबियों की ही कंपनी है। इस वजह से इस कंपनी के साथ कृषि उपज के भंडारण का अनुबंधन किया गया और फिर भारी लाभ दिया गया।

एसीबी की जाँच में भंडारण निगम से विश्वास पारीक के खिलाफ जाँच करने की अनुमति माँगी गई है, जो निगम में जनवरी 2021 से जुलाई 2024 तक निदेशक के पद पर कार्यरत रहे। यह पद वरिष्ठता में प्रबंधक निदेशक के ठीक नीचे का पद है। पारीक निगम के समस्त

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

एसआई पेपर लीक, भरतपुर से एक ट्रेनी एसआई गिरफ्तार

जयपुर, 20 मार्च। स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप की टीम ने गुरुवार को एक और ट्रेनी एसआई को भरतपुर से डिटेन किया है। एसओजी की टीम ट्रेनी एसआई वीरेन्द्र मीणा से पूछताछ कर रही हैं।

एडीजी एसओजी वीके सिंह ने बताया कि ट्रेनी एसआई से पहले पूछताछ की जाएगी। उस के बाद आगे का एक्शन लिया जाएगा। हमारी टीमें वीरेन्द्र मीणा ट्रेनी एसआई को भरतपुर पुलिस लाइन से पूछताछ के लिए लाई है। एसआई के परिजनों और अधिकारियों को इसकी जानकारी दे दी

- गहलोत सरकार के कार्यकाल के इस बहुचर्चित पेपर लीक कांड में एस.ओ.जी. एक के बाद एक नई गिरफ्तारियां कर रही है।

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)